

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2018—श्रावण 12, शक 1940

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, वित्त विभाग एवं पेंशन निराकरण समिति के कार्य को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, सार्वजनिक उपक्रम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री जीवन किशोर ध्रुव, भा.प्र.से. (2011), अपर कलेक्टर, राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, कबीरधाम के पद पर पदस्थ करता है।

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2018

क्रमांक ई 1-11/2018/एक-2.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 36/01/2018-EO (SM-I), दिनांक 19-06-2018 द्वारा श्री बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम, भाप्रसे (सीजी:1987), की सेवाएं जम्मू एवं कश्मीर शासन के विकल्प पर सौंपी गई हैं।

2. भारत सरकार के उक्त आदेश के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा श्री बी.व्ही.आर., सुब्रमण्यम, भाप्रसे (सीजी:1987), अपर मुख्य सचिव, गृह, जेल, परिवहन विभाग एवं परिवहन आयुक्त की सेवायें, जम्मू एवं कश्मीर शासन को सौंपी जाती हैं एवं श्री बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम को नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से अपने वर्तमान दायित्वों से कार्यमुक्त किया जाता है।

3. श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), प्रमुख सचिव, वित्त तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर), विभाग, प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, गृह, जेल, परिवहन विभाग एवं परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 जून 2018

क्रमांक बी-1-2/2018/एक/4.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित तहसीलदारों/अधीक्षक, भू-अभिलेख/आयुक्त तथा कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर (पे बैंड रुपये 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 में पदोन्नत करते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सामने कॉलम (4) में दर्शाये अनुसार पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री वहीदुरहमान	अधीक्षक, कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख, बिलासपुर.	डिप्टी कलेक्टर, जिला-सूरजपुर.
2.	श्री रामशीला लाल	अधीक्षक, कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख, सरगुजा.	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज.
3.	श्री अरूण कुमार सोनकर	तहसीलदार, राजनांदगांव	डिप्टी कलेक्टर, जिला-दुर्ग
4.	श्रीमती गीता शुक्ला (दीवान)	तहसीलदार, पटवारी प्रशिक्षण शाला, रायपुर.	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर.
5.	श्रीमती लता उर्वसा	तहसीलदार, बिलासपुर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव
6.	श्री संदीप ठाकुर	तहसीलदार, बलैदाबाजार-भाटापारा	क्षेत्रीय उपायुक्त, भू-अभिलेख, बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	श्री जयशंकर उरांव	विशेष सहायक, मान. मंत्री, आ.जा. तथा अनु. जा.वि., पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास एवं स्कूल शिक्षा.	यथावत्
8.	श्रीमती शारदा अग्रवाल	तहसीलदार, दुर्ग	प्रबंधक, छ.ग. राज्य भंडार गृह निगम, रायपुर.
9.	श्री देवसिंह उईके	तहसीलदार, बेमेतरा	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बेमेतरा
10.	श्रीमती सरस्वती बंजारे	तहसीलदार, जांजगीर-चांपा	डिप्टी कलेक्टर, जिला-रायगढ़
11.	श्री अमित कुमार गुप्ता	तहसीलदार, बिलासपुर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-सरगुजा.
12.	श्रीमती पूनम शर्मा	तहसीलदार, एन.आर.डी.ए. रायपुर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-रायपुर
13.	श्री जागेश्वर कुमार कौशल	तहसीलदार, दुर्ग	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर
14.	श्री प्रकाश कुमार टंडन	तहसीलदार, दुर्ग	डिप्टी कलेक्टर, जिला-कबीरधाम
15.	कु. गीता रायस्थ	तहसीलदार, कांकेर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-दुर्ग
16.	श्री प्रताप कुमार ठाकुर	तहसीलदार, बलौदाबाजार-भाटापारा	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.
17.	श्री आर. के. दीक्षित	अधीक्षक, जिला कार्यालय, रायपुर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-रायपुर
18.	श्री सी. एल. झोलपे	अधीक्षक, संभागायुक्त कार्यालय, दुर्ग	डिप्टी कलेक्टर, जिला-कांकेर

2. उपरोक्त पदोन्नतियां दो वर्ष की स्थानापन्नता अवधि के लिए होगी.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. आर. ठाकुर, उप-सचिव.

## वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2018

क्रमांक एफ 02-07/2018/10-1/वन.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को वनक्षेत्रपाल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पुनरीक्षित वेतन के लेवल 09 में (वेतनबैंड रुपये 9300-34800, ग्रेड वेतन 4300/-) पदोन्नत करते हुए वर्तमान पदस्थापना स्थान कॉलम 03 से कॉलम-04 में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक

पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री जी. नागभूषणम्, उप वनक्षेत्रपाल.	सा.वा.वनमंडल, जगदलपुर	परिक्षेत्र अधिकारी, विशेष कर्तव्य, वनमंडल जगदलपुर. से.नि.दि. 30-06-2018.
2.	श्री गोपीनाथ पाण्डे, उप वनक्षेत्रपाल.	बस्तर वनमंडल	परिक्षेत्र अधिकारी, विशेष कर्तव्य, बस्तर वनमंडल. से.नि. दि. 30-06-2018.
3.	श्री कृष्ण कुमार सुमन, उप वनक्षेत्रपाल.	बिलासपुर वनमंडल	परिक्षेत्र अधिकारी, विशेष कर्तव्य, बस्तर बिलासपुर वनमंडल, से.नि. दि. 30-06- 2018.
4.	श्री सोहन लाल नेताम, उप वनक्षेत्रपाल.	उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद.	परिक्षेत्र अधिकारी, विशेष कर्तव्य, गरियाबंद वनमंडल से.नि.दि. 30-06-2018.
5.	श्री के. के. वर्मा, उप वनक्षेत्रपाल.	बलौदाबाजार वनमंडल	परिक्षेत्र अधिकारी, विशेष कर्तव्य, बलौदा- बाजार वनमंडल. से.नि.दि. 30-06-2018.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.
3. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थिति स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा.
4. यदि पदोन्नति अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच/लोकयुक्त/आर्थिक अपराध आदि के प्रकरण लंबित हो तो उसे पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाकर, संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल उसकी सूचना शासन को दी जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. एन. राजूरकर, अवर सचिव.

### वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 20-36/2014/11/6.—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 में प्रावधानित निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिये राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

(एक) औद्योगिक नीति 2014-19 की कंडिका 4.1.9 को यथावत् बनाये रखते हुये निम्नानुसार उप-पैरा जोड़ा जाये :—

“उक्त आरक्षित 20 प्रतिशत भूमि में से 5 प्रतिशत भूमि निःशक्तजनों उद्यमियों हेतु प्रथम विज्ञापन दिनांक से 3 वर्ष तक के लिये आरक्षित रखी जायेगी. 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त आरक्षित भूमि के शेष बचे भूखण्डों को अन्य वर्गों के उद्यमियों को आबंटित किया जा सकेगा.”

(दो) औद्योगिक नीति 2014-19 की कंडिका 15.5 में से निःशक्त शब्द विलोपित कर शेष को यथावत् बनाये रखते हुये निम्नानुसार उप-पैरा जोड़ा जाये :—

“औद्योगिक नीति 2014-19 की कंडिका 15.3 अनुसार सामान्य उद्यमियों को देय अनुदान से निःशक्त व्यक्तियों को उद्योग की स्थापना पर 25 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 25 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी.”

(तीन) औद्योगिक नीति 2014-19 की कंडिका 15.12 को यथावत् बनाये रखते हुये निम्नानुसार उप-पैरा जोड़ा जाये :—

“मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों में से 5 प्रतिशत लक्ष्य निःशक्तजन उद्यमियों हेतु आरक्षित रहेगा किन्तु इस वर्ग के उपयुक्त उद्यमी वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास तक उपलब्ध न होने की दशा में लक्ष्य की पूर्ति अन्य वर्गों के उद्यमियों से की जा सकेगी.”

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

**वित्त विभाग**  
( वित्त आयोग प्रकोष्ठ )  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2018

क्रमांक 180/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-इ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र., नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2018 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में दिनांक 31 मई, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 तक वृद्धि करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश कुमार सिसोदिया, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2018

क्रमांक 180/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 180/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 29-05-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश कुमार सिसोदिया, उप-सचिव.

Raipur, the 29th May 2018

No. 180/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC.—In exercise of the powers conferred by Articles 243-I of the Constitution of India and in supersession of this department's Notification No. 16/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC, Naya Raipur, dated 29th January, 2018 the Governor of Chhattisgarh, hereby, extends the tenure of the State Finance Commission from 31st May, 2018 to 30th September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
RAJESH KUMAR SISODIYA, Deputy Secretary.

## आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 1-32/2014/32.—यतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 317 (अ), दिनांक 29 जून, 2018 के द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.) का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना में निर्देशित किया गया है कि :—

01. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिये एक अधिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन तथा उनके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी;
02. राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.) के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसरण में संदेय होंगे।
2. अतः राज्य शासन, राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.) के दायित्वों एवं कर्तव्यों के सम्यक रूप से निर्वहन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नया रायपुर को सचिवालय के रूप में अधिसूचित करता है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ तथा एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के सचिवालय हेतु पृथक से स्वतंत्र व्यवस्था करेगा।
3. राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.) हेतु सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन (Logistic Support) जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन और उसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं, अध्यक्ष तथा सदस्यों का बैठक के लिए फीस और यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता आदि का भुगतान राज्य शासन सम्बद्ध नियमों के अनुसार संदेय होंगे।

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 8-19/2017/32.—रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 के अंतर्गत ग्राम डुमरतालाब पटवारी हल्का क्रमांक 104/35, राजस्व निरीक्षक मंडल रायपुर स्थित भूमि खसरा 83/5 जो कि रेल्वे की भूमि है एवं खसरा क्रमांक 77,83/8, 83/7, 83/6, (83/4, 99/2) एवं 83/1 कुल रकबा 1.503 हेक्टेयर भूमि मेसर्स फारच्युन बिल्डकान, रायपुर की है। रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उक्त भूमि का भू-उपयोग वाणिज्यिक हेतु आरक्षित है। आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में बताया कि प्रश्नाधीन स्थल तक केवल 09 मीटर चौड़ा मार्ग उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। जबकि वाणिज्यिक भू-उपयोग हेतु न्यूनतम 12 मीटर मार्ग आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय विकास योजना बनी थी, उस समय संभवतः पहुंच मार्ग आदि के प्रावधान को ध्यान में नहीं रखा गया होगा तथा उक्त भूमि के आसपास आर.ओ.बी. होने के कारण विकास योजना में प्रस्तावित उक्त वाणिज्यिक क्षेत्र का विकास भी संभव नहीं है। आवेदित भूमि से लगकर अन्य खसरों का भू-उपयोग वाणिज्यिक है जिसके लिए पहुंच मार्ग एम.आर. 22/ए (30 मीटर) प्रस्तावित है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि से लगकर चारों ओर आवासीय विकास हुआ है। अतः उक्त स्थिति में आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ने उक्त भूमि को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 35 (2) के अंतर्गत विकास योजना में दर्शित आरक्षण से निकाल दिए जाने का प्रस्ताव किया है।

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 35(2) के प्रावधानों के अंतर्गत समाधान होने के पश्चात् राज्य शासन एतद्वारा ग्राम डुमरतालाब पटवारी हल्का क्रमांक 104/35, राजस्व निरीक्षक मंडल रायपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 83/5 खसरा क्रमांक 77,83/8, 83/7, 83/6, (83/4, 99/2) एवं 83/1 कुल रकबा 1.503 हेक्टेयर को रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में वाणिज्यिक भू-उपयोग से निकाल दिए जाने की मंजूरी देता है।

3. इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रश्नाधीन भूमि रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में दर्शित आरक्षण से निर्मुक्त हुई समझी जावेगी, और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास के प्रयोजन के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेजीना टोप्पो, अपर-सचिव.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 4 जुलाई 2018

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/11509/क/भू-अर्जन/04 अ/82/2017-18.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला उप तह. बरपाली	कनकी	0.544 हे.	तेन्दूवाही व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 01-08-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम कनकी नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	तेन्दूवाही व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	245.52 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई हेतु
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होन वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा द्वारा राशि 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 263204 दिनांक 11-06-2018 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 20 जुलाई 2018

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/12523/क/भू-अर्जन/22 अ/82/2017-18.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला उप तह. बरपाली	तरदा	1.445 हे.	गंगदेई व्यपवर्तन योजना का बांयी तट मुख्य नहर निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-08-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम तरदा नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	गंगदेई व्यपवर्तन योजना का बांयी तट मुख्य नहर निर्माण
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	28
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	590.25
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई हेतु
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होन वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा द्वारा राशि 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 263221 दिनांक 11-07-2018 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मो. कैसर अब्दुल हक**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.



**कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग**

महासमुंद, दिनांक 17 जुलाई 2018

क्रमांक 171/भू-अर्जन/16 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	दाईजबांधा प.ह.नं. 48	0.70	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**हिमशिखर गुप्ता**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 3 जुलाई 2018

क्रमांक/11421/भू-अर्जन/23 अ 82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	बरपाली प.ह.नं. 04	0.040	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोरबा.	बरपाली-तुमान मार्ग निर्माण में छूटे हुए भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 जुलाई 2018

क्रमांक/11933/अ-82/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंडीउपरोड़ा	आमाखोखरा प.ह.नं. 36	3.117	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजनांतर्गत शीर्ष निर्माण कार्य के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोंडीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रा.गंज छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व  
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 29 मई 2018

क्रमांक/3457/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	कुसमी	घुटराडीह प.ह.नं. 14	19.058	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग - बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रा.गंज.	बेनगंगा जलाशय योजना ग्राम घुटराडीह.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 29 मई 2018

क्रमांक/3458/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	कुसमी	नटवरनगर प.ह.नं. 14	13.811	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग - बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रा.गंज.	बेनगंगा जलाशय के डूबान क्षेत्र एवं मुख्य नहर एवं बेस्ट बियर योजना ग्राम नटवरनगर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 29 मई 2018

क्रमांक/3459/अ-82/2017-2018.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	रामानुजगंज	पुटसुरा प.ह.नं. 17	1.97	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, क्रमांक-2, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर - रामानुजगंज (छ.ग.).	खुटपाली व्यपवर्तन योजना के चिरकोमा डिस्ट्रीब्यूटरी के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 29 मई 2018

क्रमांक/3460/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	रामानुजगंज	चिरकोमा प.ह.नं. 26	1.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, क्रमांक-2, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर - रामानुजगंज (छ.ग.).	खुटपाली व्यपवर्तन योजना के चिरकोमा डिस्ट्रीब्यूटरी के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 29 मई 2018

क्रमांक/3461/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	रामानुजगंज	महराजगंज प.ह.नं. 25	1.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, क्रमांक-2, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर - रामानुजगंज (छ.ग.).	खुटपाली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 29 मई 2018

क्रमांक/3462/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	रामानुजगंज	पीपरसोंत प.ह.नं. 17	1.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, क्रमांक-2, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर – रामानुजगंज (छ.ग.).	उबका जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 29 मई 2018

क्रमांक/3463/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	रामानुजगंज	चन्दपुर प.ह.नं. 17	9.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, क्रमांक-2, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर – रामानुजगंज (छ.ग.).	उबका जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हीरालाल नाथक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 11 जुलाई 2018

क्रमांक/1959/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोण्डागांव  
(ख) तहसील-माकड़ी  
(ग) नगर/ग्राम-केरावाही  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.093 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
409	0.016
356/2	0.518
410	0.081
411/1	0.223
349/1, 373/4	0.283
349/2, 373/4	0.324
412	0.243
413	0.170
414/1	0.154
414/2	0.182
348/1	0.202
415/1	0.121
416/1	0.385
415/2, 416/3	0.372
350/2	0.202
415/3, 416/4	0.143
416/2	0.174
417/1	0.506
417/2	0.202
348/2	0.020
349/3, 373/4	0.405
350/1	0.405

(1)

(2)

351/1	0.255
351/2क	0.126
351/2ख	0.126
352/1	0.405
352/2	0.101
352/3	0.101
353, 355	0.648

योग

29

7.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केरावाही जलाशय बांध निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीलकंठ टेकाम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 11 जुलाई 2018

क्रमांक/11915/भू-अर्जन/49 अ 82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा  
(ख) तहसील-कोरबा  
(ग) नगर/ग्राम-पसरखेत  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
16/2	0.05

(1)	(2)	कोरबा, दिनांक 11 जुलाई 2018	
276, 277	0.24	<p>क्रमांक/11930/भू-अर्जन/51 अ 82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—</p> <p style="text-align: center;"><b>अनुसूची</b></p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला-कोरबा</p> <p>(ख) तहसील-कोरबा</p> <p>(ग) नगर/ग्राम-चचिया</p> <p>(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.82 एकड़</p>	
269	0.42		
271	0.24		
208/2	0.03		
200	0.02		
260, 268/2	0.22		
181	0.14		
270/1	0.17		
270/2, 275/3	0.18		
221/3	0.03		
270/3	0.17		
265	0.17		
261, 267/2	0.10		
211/3	0.08		
211/5, 213/1	0.25		
211/4	0.45		
208/1, 211/2	0.18		
214	0.10		
207	1.33		
168/2, 199	0.22	खसरा नम्बर	रकबा
221/4	0.20	(1)	(एकड़ में) (2)
222/2	0.06	313	0.53
223/2	0.13	321	0.20
223/9	0.25	322	0.04
164/1, 166/1	0.24	323/1	0.23
170, 171/2	0.12	229/1	0.11
169	0.46	209/1	0.17
174	0.21	155	0.26
149/7, 147/1	0.31	164/8	0.62
183/1, 184/1	0.02	164/7	0.22
176, 177	0.15	165/2	0.26
149/10	0.25	166/1	0.04
175, 182	0.20	167/1	0.25
178	0.60	615/3	0.16
148/1, 149/9	0.35	609/5	0.12
147/2, 149/17	0.08	609/26	0.01
281/5, 282/5, 283/7, 285/3	1.00	750/1	0.11
281/6, 282/4, 283/2	0.45	750/2	0.11
योग	39	609/1	0.21
		648/1	0.21
		648/2	0.09
		609/6	0.16
		609/4	0.14
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धवन नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.		626/1	0.14
		626/3	0.13
		627/1	0.14
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.		657/1	0.07
		637/1	0.36

(1)	(2)
628	0.11
649	0.21
647	0.16
646	0.23
636, 637/4	0.05
637/3	0.20
749	0.23
748	0.16
782	0.20
788	0.18
योग	37 6.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धवन नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 जुलाई 2018

क्रमांक/12527/भू-अर्जन/39 अ 82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कुदुरमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
156	0.63
157	0.33
161	0.80
158	0.32

(1)	(2)
159	0.25
162	0.30
160	0.44
163	0.40
165	0.40
योग	9 3.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुदुरमाल एनीकट योजना के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मो. कैसर अब्दुल हक**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़  
शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 12 जुलाई 2018

प्रकरण क्रमांक/6219/04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-लट्टीडेरा (बनबगौद)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.02
15	0.04
18	0.06
14	0.05



(1)	(2)	अनुसूची
16	0.09	(1) भूमि का वर्णन-
8	0.03	(क) जिला-धमतरी
17	0.04	(ख) तहसील-नगरी
21	0.05	(ग) नगर/ग्राम-बनबगौद
20	0.07	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर
43	0.04	
योग	10	0.49
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फुटहामुड़ा मुख्य निर्माण योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु.		खसरा नम्बर (1)
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.		रकबा (हेक्टेयर में) (2)
		543 का टुकड़ा 0.30
		योग 1 0.30
धमतरी, दिनांक 12 जुलाई 2018		
प्रकरण क्रमांक/6223/03/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फुटहामुड़ा मुख्य निर्माण योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.		
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.		

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड  
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/2485.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/4170 रायपुर, दिनांक 01-10-2016 द्वारा श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, अंबिकापुर को कृषि उपज मण्डी समिति अंबिकापुर, जिला-सरगुजा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय अंबिकापुर के पत्र क्रमांक 201 दिनांक 07-06-2018 द्वारा श्री मनीराम भगत, उप संचालक, कृषि, अंबिकापुर को कृषि उपज मंडी समिति अंबिकापुर, जिला-सरगुजा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, अंबिकापुर के स्थान पर श्री मनीराम भगत, उप संचालक, कृषि अंबिकापुर, को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति अंबिकापुर, जिला-सरगुजा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/2487.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/6820 रायपुर, दिनांक 28-01-2017 द्वारा श्री गंगाधर वाहिले, डिप्टी कलेक्टर को कृषि उपज मण्डी समिति गरियाबंद, जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय रायपुर के पत्र क्रमांक 921 दिनांक 13-06-2018 द्वारा श्री आर. एस. ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विस्तार, अधिकारी गरियाबंद को कृषि उपज मण्डी समिति गरियाबंद, जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री गंगाधर वाहिले, डिप्टी कलेक्टर के स्थान पर श्री आर. एस. ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विस्तार, अधिकारी गरियाबंद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति गरियाबंद, जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अभिजीत सिंह,  
प्रबंध संचालक.

### मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2018

क्रमांक 2952/07/2018/स्था./छ.ग.प.सं.मं./2018.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, (1974 की संख्या 6) की धारा 12 की उपधारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

#### संशोधन

अनुसूची-एक के सरल क्रमांक “(घ) जनसंपर्क सेवायें” के पश्चात् निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाएं,

#### (ङ) विधिक सेवायें

1	विधि अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स - 13
2	सहायक विधि अधिकारी	2	द्वितीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स - 12

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक “(घ) जनसंपर्क सेवायें” पश्चात् निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाए,

( ड ) विधिक सेवायें

1	विधि अधिकारी	1	—	100 प्रतिशत
2	सहायक विधि अधिकारी	2	100 प्रतिशत	—

3. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक “(3) सहायक जनसंपर्क अधिकारी” के पश्चात् निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाए,

( ड ) विधिक सेवायें

4	सहायक विधि अधिकारी	तदैव	तदैव	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 05 वर्षीय एल.एल.बी. की उपाधि.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा गठित चयन समिति.
---	--------------------	------	------	---	--

4. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक “(घ) जनसंपर्क सेवायें” के पश्चात् निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाए,

( ड ) विधिक सेवायें

1	सहायक विधि अधिकारी	विधि अधिकारी	सहायक विधि अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की निरंतर सेवा.	तदैव
---	--------------------	--------------	---	------

संजय शुक्ला,  
सदस्य सचिव.